



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 22, 1980/पौष 1, 1902

No. 575]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 22, 1980/PAUSA 1, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(प्रौद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1980

का.० अ.० 982(अ)/18 च ख/प्राइडेंस/एए/80.—केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (किकार और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उद्योग मंत्रालय (शीर्षोंगत विकास विभाग) के द्वारा उद्योग नं. का.० 826 (अ)/18 च ख/प्राइडेंस द्वारा पा/76, नारीबाल 23 दिसम्बर, 1976 (जिसे इसके पश्चात उक्त आदेश को द्वारा दिया गया है) द्वारा वांचित किया था कि उक्त आदेश के आगे होने की नारीबाल से ही पूर्व प्रवृत्त नभी या किसी संविदा, सम्पत्ति, हास्तांतरण पत्रों, कागजों, व्यवस्थापनों, पासों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों (महानगर भरकार वारा प्रत्याखृत स्पष्ट नकद प्रत्यय सीमा के अधीन पराये रखने के विस्तार तक भारतीय स्टेट बैंक के प्रति दायित्वों को और नकद प्रत्यय लेना (माध्यमण) में से मिल द्वारा निकाली गई रकमों की, जहां तक कि वे असामत आमियों के अन्तर्गत हैं, छोड़कर) का प्रयोग, जिनका मैमर्स पुनर्गाव काठन मिल निमिट्ट, पुनर्गाव नामक शीर्षोंगत उपकरण एवं पक्षकार है, या जो उक्त प्रौद्योगिक उपकरण का लागू हो रहते हैं, ऐसी नारीबाल में एक वर्ष की प्रत्यधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त नारीबाल से पूर्व उनके अधीन प्रोद्भूत या उद्भुत नभी श्रिविद्या, विशेषाधिकार, वाधानांग और वायन्त्र उक्त प्रत्यधि के लिए निर्मिता रहेंगे;

और उक्त आदेश की प्रवधि समय-समय पर विस्तारित की जाती रही है, जिसमें ऐनिम विस्तारण 22 दिसम्बर, 1980 तक, जिसमें यह नारीबाल भी सम्मिलित है, के लिए था;

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की प्रवधि तीन मास के लिए और विस्तारित कर दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 च ख का उपधारा (2) के माध्य पठित उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश को अवधि 22 मार्च, 1981 तक, जिसमें यह नारीबाल भी सम्मिलित है, के लिए और विस्तारित करनी है।

[फा.० स० 3(17)/75सीयूएस]

जी० नौ० गमालूणा, प्रतिरक्षित सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 1980

S.O. 982(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 826(E)/18FB/IDRA/76 dated the 23rd December, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section

(1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operations of all or any of the contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than the liabilities to the State Bank of India to the extent of the amount outstanding on the clean cash credit limit guaranteed by the Government of Maharashtra and the amounts drawn by the mill against the cash credit account (ordinary) to the extent these are covered in the current assets) to which the industrial undertaking known as Messrs. Pulgaon Cotton Mills Limited, Pulgaon, is a party or which may be applicable to the said industrial undertaking shall remain suspended for a period of one year from such date and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And whereas the duration of the said Order was extended from time to time, the last of such extensions being upto and inclusive of the 22nd December, 1980 ;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of three months ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 22nd March, 1981.

[File No. 3(17)/75-CUS]

G. V. RAMAKRISHNA, Additional Secy.